International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 9 Issue 1 Ser. II || Jan 2020 || PP 82-86

भारत की बदलती विदेश नीति

डॉ० बी० बी० सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग
राजनीति विज्ञान हिन्दू कॉलेज मुरादाबाद

परिचय

भारतीय विदेश नीति के निर्धारण और बाध्यताएँ भारत विश्व में एक विस्तृत भू-भाग तथा विशाल जनसंख्या वाला देश है अतः इसकी विदेश नीति का विश्व राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है । भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए जवाहरलाल ने सितंबर 1946 में यह कहते हुए उदघोष किया था, "वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्म-निर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा ।"

नेहरू का यह कथन आज भी भारत की विदेश नीति का आधारस्तंभ है । भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है जिसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढावा देगा, राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाये रखने का प्रयास करेगा राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करेगा तथा राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगडों को पंच फैसलों द्वारा निपटाने की रीति को बढावा देगा ।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत के विदेश संबंधों का कार्यान्वयन निम्नलिखित प्रमुख सिद्धातों से संचालित रहा है:

(i) भारत की प्रभुसत्तात्मक स्वतंत्रता की रक्षा ।

(ii) शक्ति गुटों से दूर रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण ।

(iii) परतंत्र लोगों की स्वतंत्रता के सिद्धांत की स्वीकृति एवं साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद का विरोध ।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा समृद्धि के लिए सब शांतिप्रिय देशों तथा संयुक्त राष्ट्र से सहयोग ।

(v) विश्व तनाव में कमी करना ।

(vi) न्याय तथा ईमानदारी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तथा सहयोग का अधिक समान ढाँचा बनाना ।

(vii) विश्व राजनीति में समान भागीदारिता की प्राप्ति के लिए तीसरे विश्व में एकता तथा भाईचारे को प्रोत्साहित करना ।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारत गुटनिरपेक्षता तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर चलता रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भाग लेता रहा है ।

भारत की विदेश नीति क्या है

भारत की विदेश नीति समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। विदेश नीति निर्धारण का उद्देश्य अपने पड़ोसियों तथा शेष विश्व के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करना है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर निर्णय लेने की स्वायत्तता को सुरक्षित करना है। हमारी विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत हैं-सामाजिक-आर्थिक विकास एवं राजनीतिक स्थिरता जैसे राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना, विभिन्न देशों के बीच शांति, मित्रता, सद्इच्छा एवं सहयोग को बढ़ावा देना, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं निरंकुश शक्तियों का प्रतिरोध करना तथा अन्य देशों के आंतरिक मामलों में विश्व के सर्वाधिक शक्तिफ़शाली देशों द्वारा हस्तक्षेप का विरोध करना। इसके अलावा राष्ट्रों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना, शस्त्रीकरण का विरोध करना एवं निःशस्त्रीकरण अभियान का समर्थन करना, मानवाधिकारों का सम्मान करना एवं जाति, प्रजाति, रंग, नस्ल, धर्म इत्यादि पर आधारित भेदभाव एवं असमानताओं का विरोध करना तथा पंचशील एवं गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों को प्रोत्साहित करना।

पृष्ठभूमि

भारत की विदेश नीति की बात करें तो भारत की स्वतंत्रता से पूर्व ही राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेताओं ने इसमें रुचि लेने तथा भारत के भविष्य का निरूपण करना शुरू कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने 1927 में जवाहर लाल नेहरू को अपना प्रवक्ता बनाकर विदेश नीति विभाग की स्थापना कर ली थी। स्वतंत्रता के बाद पं- जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति आगे बढ़ी। पं. नेहरू की नीति गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित थी। अर्थात वह किसी भी विशेष गुट में शामिल होने के बजाय अपनी स्वतंत्र सोच में विश्वास करते थे। चूंकि केन्द्र में लम्बे समय तक काँग्रेस की सरकार रही इसलिए यही नीति प्रभावी रही। वर्ष 1977 में केन्द्र में जनता दल की सरकार बनने के बाद भी देश की विदेश नीति के मूल सिद्धांत बिना किसी मौलिक परिवर्तन के जारी रही।

वर्ष 1990 तक आते-आते देश की विदेश नीति का एक नया दौर आया। यह वह दौर था जब दुनिया एक युगान्तकारी घटना से गुजर रही थी, जिसे भूमंडलीकरण के नाम से जाना जाता है। दरअसल वर्ष 1991 में द्विध्रुवीय विश्व समाप्त हो गया। अब शक्ति का एक मात्र केन्द्र अमेरिका था क्योंकि दूसरा ध्रुव जिसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था का विघटन हो गया था। इस दौर में भारत का झुकाव धीरे-धीरे अमेरिका की तरफ होने लगा। हालांकि भारत ने रूस से भी अपने संबंधों को बनाये रखा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भारत की विदेश नीति का एक स्वर्णिम युग रहा और भारत ने विश्व के साथ बेहतर जुड़ाव में सफलता हासिल की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के सरकार में भी भारत ने विदेश नीति के क्षेत्र में कई सफलताएँ हासिल कीं। वर्तमान सरकार की विदेश नीति भी वसुधैव कुटुम्बकम् के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि वर्तमान सरकार की नीति में पड़ोसी प्रथम और आर्थिक आयाम के पहलू ज्यादा हैं।

भारत की वर्तमान विदेश नीति

वर्तमान सरकार की विदेश नीति के अंतर्गत वैश्विक शक्तियों के साथ आगे बढ़ने और अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करते हुए भारत के सामरिक स्वायत्तता को बनाये रखना है। वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों से परस्पर संवाद के माध्यम से विदेश नीति को पुनर्परिभाषित किया गया है। भारत की वर्तमान विदेश नीति दूसरे देशों से केवल रक्षा उत्पादों की खरीद तक सीमित नहीं है बल्कि तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भारत विकसित देशों के साथ प्रयत्नशील है। वर्तमान में भारत अपने सामरिक हितों की पूर्ति के लिए अमेरिका और रूस को संतुलित रूप से साथ लेकर चल रहा है। सामरिक के साथ-साथ वाणिज्यिक हितों की पूर्ति के लिए भारत अपने पड़ोसी देशों पर फोकस कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि पहले विदेशी दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रणनीतिक रूप से हिंद महासागर के द्वीपीय देश मालदीव को चुना । पिछले चुनाव में मालदीव की जनता ने चीन समर्थित सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। हालांकि उससे पहले ही वहाँ की सरकार कई छोटे-छोटे द्वीप, चीन को पट्टों पर दे चुकी थी। मालदीव में लोकतंत्र बहाली के बाद से भारत ने उसे पूरी उदारता से वित्तीय मदद मुहैया कराई है। इससे मालदीव को चीनी कर्ज के जाल से निकलने में मदद मिली है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने एक और सराहनीय कदम उठाते हुए अपने शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल की खाड़ी से सटे बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग परिषद पहल यानी बिम्सटेक के सदस्य देशों को आमंत्रित किया। बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली कड़ी है। इसमें भारत की 'पड़ोसी को प्राथमिकता' और 'एक्ट ईस्ट' नीति भी एकाकार होती है। इसके उलट दक्षेस का दायरा भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित है, जबकि बिम्सटेक भारत को उसकी ऐतिहासिक धुरियों से जोड़ता है।

वर्तमान परिदृश्य में देखें तो ज्ञात होता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के सामने बड़ी सामरिक चुनौती पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और चीन के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए शी चिनफिंग को 'अनौपचारिक सम्मेलन के लिए भारत आमंत्रित किया । इसके पहले संबंधों में तल्खी दूर करने के लिए चीन के वुहान में दोनों नेता ऐसी एक बैठक कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका से रिश्ते बेहतर होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को साध पाना भारत के लिए खासा चुनौतीपूर्ण होगा। ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने से ट्रंप पहले ही भारत पर बोझ बढ़ा चुके हैं।

यह स्वीकार करते हुए कि किसी भी देश की विदेश नीति केवल नई सरकार आ जाने से अपने पुराने संबंधों को तोड़ नहीं देती। वर्तमान सरकार की 'पड़ोस पहले' नीति कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की दशकों पुरानी नीति के अनुसार ही है, जिसने भारत के पड़ोसियों के साथ दोस्ती पर जोर दिया था। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आई । इसी तरह, अफगानिस्तान के साथ संबंध दोस्ताना ही रहे हैं, जहाँ आम जनता के सकारात्मक भाव से रिश्तों में बढ़ोतरी हुई और उन्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया ।

श्रीलंका के साथ वर्तमान सरकार के संबंध निश्चित रूप से परंपरा से हट कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से स्थिर भारत सरकार ने भारत-श्रीलंका संबंधों को सफलतापूर्वक तमिल राजनीति से अलग निकाल कर उन्हें सांस्कृतिक एकता के दायरे में लाया। हालाँकि 2015 से भारत-समर्थक मैत्रीपाल सिरीसेना सरकार के सत्ता में होते हुए भी, श्रीलंका द्वीप पर भारत चीन की रणनीतिक जगह को कम करने में बहुत सफल नहीं रहा है, जो आशा के विपरीत है। नेपाल और पाकिस्तान इस क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी चुनौती को रखांकित करते हैं। पाकिस्तान के साथ संबंध सख्त गतिरोध में फंसे हैं। ये संबंध 2008 के मुंबई हमलों के बाद से सबसे अधिक कटुतापूर्ण स्थिति में हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, 2016 के अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी का बलूचिस्तान का उल्लेख, कुलभूषण जाधव विवाद, पठानकोट, उरी हमला तथा भारत द्वारा बालाकोट में एयर स्ट्राइक आदि ने दोनों देशों के रिश्तों में अधिक दूरियाँ पैदा की हैं। नेपाल में 2015 के भूकंप के बाद भारत की मदद और समर्थन के होते हुए भी, नेपाल के नए संविधान ने काठमांडू और नई दिल्ली के बीच दरार पैदा की और मधेसी आंदोलन के कारण यह दरार और भी चौड़ी हो गई है। पिछले कुछ वर्षों से संकेत मिलता है कि नेपाल में भारत का प्रभाव कम हो रहा है और चीन भारत की जगह लेने को इच्छुक है। इस संबंध में भारत नेपाल को साधने के प्रयास में लगा हुआ है।

मॉरीशस और सेशेल्स के द्वीप देशों की यात्रा और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के साथ संबंध बनाने के अलावा, भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में एक मजबूत नींव बनायी है। ऊर्जा, सामरिक और आर्थिक मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे महत्वपूर्ण थे और इन दौरों ने हिंद महासागर में भारत की समुद्री भूमिका पर जोर दिया। आईओआर में नई दिल्ली की विदेश नीति को एक विशेष प्रोत्साहन मिला जब जनवरी 2016 में विदेश मंत्रलय में एक अलग आईओआर डिवीजन की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री मोदी की पहल से दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' में नयापन और सामरिक गंभीरता आई, जो 1990 के दशक की नीति का पुनर्जागृत रूप है। यह केवल नाम का परिवर्तन नहीं है बल्कि यह एक्ट ईस्ट दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने में भारत की उत्सुकता को भी दर्शाती है।

भारत की विदेश नीति में आए बदलाव से भारत और जापान के बीच संबंध गहरे हुए हैं और ये संबंध 2015 में बढ़ कर 'विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी' तक पहुँच गए हैं। भारत और जापान के बीच निर्बाध समन्वय, अवसंरचना सहयोग, परमाणु ऊर्जा और तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को रखांकित करते हैं।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर चिंताओं के कारण भारत ने बेल्ट और रोड फोरम को छोड़ दिया और चीन पर नजर बनाए रखने के साथ, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुर्भुज सहयोग स्थापित करने के लिए वार्ता में भाग लिया।

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति भारत- अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के मामले में सफल रही, जहाँ द्विपक्षीय भागीदारी के मामले में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, आधारभूत लॉजिस्टिक समझौतों और भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर प्रगति दिखाई वही दोनों देशों के बीच संबंध साझा हितों के कारण बढ़े हैं। हालांकि इस बीच रूस के साथ संबंध प्रभावित हुए हैं क्योंकि भू-राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव के कारण भारत-अमेरिका के संबंध घनिष्ठ हुए हैं, विशेष रूप से रक्षा मामलों में, इसके विपरीत रूस, चीन और पाकिस्तान के संबंध आपस में मजबूत हुए हैं।

चुनौतियाँ

विदेश नीति के मामले में भारत की सबसे बड़ी चुनौती केवल यह नहीं होगी कि अपने पड़ोसियों तथा आसियान एवं पश्चिम एशिया समेत दूरवर्ती पड़ोसियों को किस तरह संभाला जाए बल्कि विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को दुरुस्त करना भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

देखा जाये तो चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के कारण उसके साथ संबंध बनाए रखना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। चीन ने अपनी वित्तीय एवं सैन्य ताकत के जरिये तथा दरियादिली से खैरात बांटकर भारत के पड़ोसी देशों में अपना मजबूत प्रभाव जमा लिया है, जो हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों की राह में बाधक बन सकता है। चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति उसकी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना और बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं के लिए सटीक बैठती है। वास्तव में इससे चीन का प्रभाव और भी आगे तक चला जाता है, जो रणनीतिक रूप से हमारे लिए असहज हो सकता है। चीन ने नेपाल और श्रीलंका के साथ अपने रक्षा संबंध और भी मजबूत किए हैं जो भारत के लिए चिंता का विषय है।

चीन, रूस और भारत के पारंपरिक एवं पारस्परिक संबंधों में खटास लाने की भी कोशिश कर रहा है। रणनीतिक वैश्विक मंच पर जगह पाने के भारत के दावे का चीन द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, जैसे- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के हमारे प्रयासों को विफल करना आदि। चीन-पाकिस्तान-रूस के बीच कुछ समय पहले हुई बैठकें तथा भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले होने के बावजूद रूस-पाकिस्तान सैन्य अभ्यास इसका एक अन्य उदाहरण है।

रूस के साथ भारत के रिश्ते बहुत पुराने और विविधता भरे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के साथ भारत की बढ़ती निकटता से "भरोसेमंद और पुराने दोस्त" या "रूसी-हिंदी भाई भाई" जैसे भावनात्मक संबंधों की स्थिति जो पहले थी अब वह स्थिति नहीं है। हालाँकि भारत के साथ आर्थिक रिश्ते रूस को बेहतर संबंध बनाये रखने के लिये मजबूर कर सकते हैं क्योंकि खनिजों तथा हीरों के अलावा सैन्य उपकरणों तथा असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों के लिए भारत अब भी उसके सबसे बड़े बाजारों में शामिल है।

जहाँ तक अमेरिका की बात है, तो वहाँ भारतीय समुदाय का मजबूत प्रभाव तथा राष्ट्रपति ट्रंप की कारोबारी रुख रखने वाली टीम उसे भारत की ओर केंद्रित रखने में सहायक हो सकती है। रोजगार और विनिर्माण गतिविधियाँ वापस अमेरिका में लाने तथा कर ढाँचों में प्रस्तावित बदलावों की नीतियों से भारत में अमेरिकी वित्तीय निवेश में कमी आने की आशंका तो है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ दिक्कतें हो सकती हैं।

आगे की राह

वर्तमान सरकार की विदेश नीति एक नये आयाम के साथ आगे बढ़ रही है लेकिन कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें अभी भी किया जाना बाकी है जैसे-

1. भारत की प्रथम पड़ोस की नीति अच्छी है लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं क्षेत्रीय राजनीति में उलझकर हम अपने दूर के मित्रें की अवहेलना न कर बैठें। अतः आवश्यकता इस बात की है कि 'विश्व बंधुत्व' की भावना जो भारत की पहचान रही है उसको आगे बढ़ाया जाय।
2. वर्तमान विश्व में संबंधों के आयामों को आर्थिक आधार पर तौला जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हित के हिसाब से ही विदेश नीति को आगे बढ़ाना चाहिए।
3. वर्तमान में अमेरिका-ईरान, इजरायल- फिलीस्तीन, चीन-अमेरिका, अमेरिका-रूस आदि के बीच मनमुटाव चरम पर है। इसके बीच न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक गतिरोध भी बढ़ गये हैं। ऐसे में भारत को कोई भी कदम सोच समझकर उठाना होगा क्योंकि इन सभी देशों के साथ उसके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं।
4. आधुनिक युग में विदेश नीतियाँ प्रत्येक घंटे परिवर्तित होती रहती हैं तथा मौसम के हिसाब से रंग बदलती हैं। ऐसे में विदेश नीति का स्पष्ट होना अति आवश्यक है। जॉन एफ कैनेडी ने भी कहा था कि घरेलू नीतियों की गलतियाँ हमें हरा सकती हैं किन्तु विदेश नीतियों की गलतियाँ हमारे प्राण ले सकती हैं। विदेश नीति के संदर्भ में इस कहावत पर विचार करना होगा।
5. पाकिस्तान को कुछ समय के लिए अलग-थलग करना सही हो सकता है लेकिन दीर्घ समय के लिए यह सही नहीं है। इसलिए बात-चीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी के विकास के बिना क्षेत्र में शांति स्थापित होना असंभव है।
6. रूस हमारा पारंपरिक मित्र रहा है इसलिए अमेरिका से मजबूत रिश्ते के बावजूद रूस से बेहतर संबंध आवश्यक हैं।

7. भारत की विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि पड़ोसी देशों को लगे कि वे सब साथ मिलकर चल रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 'बिग ब्रदर्स सिंड्रोम' की स्थिति में भारत आ जाएगा जो इसके लिए सही नहीं है।
8. वर्तमान सरकार को सोचने और नये तरीके से कार्य करने का पूर्ण अधिकार है लेकिन उसे पहले की सरकारों द्वारा लागू विदेश नीति पर भी ध्यान देना होगा जिससे कि भारत अपनी वास्तविक पहचान को बनाये रख सके।
9. हमें भारत-अमेरिका-जापान त्रिपक्षीय संवाद के साथ संपर्क और भी बढ़ाना चाहिए या बेहतर होगा कि समान क्षेत्रीय उद्देश्यों वाले समूह में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर चतुर्पक्षीय संपर्क बढ़ाया जाए।

संदर्भ

1- यू आर घई- भारतीय विदेश नीति
2- वी ग्रोवर- इण्डियाज नेवर्स एण्ड हर ब्रेन पालिसी
3- अतरचन्द- एशियन सिक्यूरिटी
4- सी राधामोहन- मोदीज वर्ल्ड
5- सुमित गांगुली- भारत की विदेश नीति, पुनरावलोकन एवं संभावनाएं
6- जनसत्ता
7- राजस्थान पत्रिका
8- दैनिक जागरण
9- इण्डियन एक्सप्रेस
10- टाइम्स ऑफ इंडिया